Manufacture of Household Utensils

181. SHRI RANE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of brass and coper household utensils have touched Rs. 15 to 20 per kilo and whether these prices are 300 per cent higher as compared to the prices prevailing in 1963-64;

(b) whether it is also a fact that these prices have gone up an account of less import of brass and copper and heavy excise duty on these metals; and

(c) if so, the steps taken by Government to make these houserold utensils available at lower prices in the near future?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). Facts are being ascertained and a statement will be laid on the Table of the House.

Cotton Production

182. SHRI RANE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any estimate for the production of cotton during 1967-68 has been made;

(b) if so, the variation between the previous estimate and the recent one; and

(c) whether it is also a fact that prices of cotton have gone down on account of the curbs of credit to traders by the banks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). No official estimate has yet been made of the Indian cotton crop for the current year 1967-68. The general expection, however, is that it would be about 20 per cent over the last year's figure.

(c) No, Sir. The decline in prices of cotton of late, is essentially due to larger arrivals of cotton into the market.

Railway Orders to Engineering Firms

183. DR. RANEN: SEN: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri Hada, President, Engineering Association of India, Calcutta refuting his statement that there has been no cut in the Railway orders on engineering firms; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) The Railways have done their best to help the industry and will continue to do so, having due regard to their own requirements and the industry's actual performance. For example, while the industry had a backlog of 10575.5 wagons in terms of 4-wheelers on 1-4-1967, orders for production of 16320.5 wagons in terms of 4-wheelers during 1967-68 were placed on them, totalling 26896 4-wheelers. As against this, the actual delivery during the first 10 months (i.e. upto January, 1968) is 11653 wagons in terms of 4-wheelers. The backlog of orders with the industry expected on 31-3-1968 will be more than 12000 wagons in terms of 4-wheelers, while the Railways, as against their own estimated requirements of 10,000 wagons in terms of 4-wheelers, have placed orders for 16,000 wagons in terms of 4-wheelers for the period 1968-69, in order to keep the industry adequately engaged.

Public Undertakings in Andhra Pradesh

185. SHRI M. N. REDDY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number and places of location of public sector undertakings and industrial establishments in Andhra Pradesh; and

(b) the number and names of the industrial undertakings in Andhra Pradesh under the management of Birlas?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

जबलपुर पन्ना और रीवा रेलवे लाइन

186. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर, पन्ना और रीवा के बीच रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसकी मंजूरी 20 वर्ष पूर्व दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते क्योंकि इस क्षेत्र में रेलवे लाइनें अपर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जबलपुर, पन्ना और रीवा रेलवे लाइन के निर्माण पर विचार करेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) से (ग). अतीत में कभी भी प्रस्तावित लाइन के निर्माण की मंजूरी नहीं दी गयी थी। इस बात की जानकारी रेलों को नहीं है कि रेल परिवहन की कमी के कारण इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास में कभी कोई रुकावट आयी है। धन की कमी के कारण चौथी योजना में केवल उन्हीं अनिवार्य सम्पर्क लाइनों के निर्माण के बारे में विचार किया जा रहा है जिन्हें विकास सामरिक या परिचालन की दृष्टि से तुरन्त बनाना अपेक्षित है। अतः फिलहाल प्रस्तावित लाइन को इतनी प्राथमिकता नहीं मिल पायेगी कि उस पर विचार किया जा सके।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में उद्योग

187. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये इसमें कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग का नाम क्या है और यह कब तक स्थापित हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

188. **श्री रामसिंह अगरवाल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमोह जिले (मध्य प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि सागर और दमोह जिलों में खनिज के काफी भंडार हैं जिनसे सरकार को करोड़ों रुपये की आय हो सकती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सागर विश्वविद्यालय के व्यावहारिक भूतत्वीय केन्द्र का खनिज के इन विशाल भंडारों को निकालने में अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नवम्बर, 1964 में बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० को जिला दमोह के पथरिया नामक स्थान में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के लिये छः महीने की अवधि (जो बढ़ा कर 31.12.65 तक कर दी गई) के लिये मान्य एक आशय-पत्र जारी किया गया था। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 200,000 मीट्रिक टन थी अब सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दे दी गई है और अब सीमेंट का कारखाना लगाने अथवा पुराने आशय पत्रों की मान्यता की